नवभारत टाइम्स, पृष्ठ 5, 27-4-16

कृषि मंत्री ने कहा, सूखे पर कराएं चर्चा

■विस/पीटीआई, नई दिल्ली : सूखे पर प्रश्नोत्तर काल के दौरान कृषि मंत्री राधामोहन सिंह विपक्ष की टोकाटाकी से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सदन में अपनी ही सरकार से मांग कर डाली कि सूखे पर विस्तार से चर्चा हो, ताकि सारे तथ्य लोगों के सामने आएं। दरअसल, प्रश्नोत्तर काल के दौरान जब सूखे की स्थिति पर सवाल-जवाब हो रहे थे, तभी कांग्रेस के राजीव सातव ने महाराष्ट्र में सूखे को लेकर सवाल किया और जब मंत्री जवाब दे रहे थे, तभी उन्होंने बीच में अपनी बात कही। इससे कृषि मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि वे मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में सूखे पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि सारे तथ्य जनता के सामने आएं और सिंचाई के नाम पर हुई बंदर बांट का भी पता चले।

इससे पहले कृषि मंत्री ने कहा कि सूखे के मामले में पिछले साल ही बैंकों को निर्देश दिए गया था कि जहां भी फसल का 30 फीसदी नुकसान हुआ है, वहां पुर्नभुगतान की अवधि दो वर्ष और जहां 50 फीसदी फसल का नुकसान हुआ है, वहां भुगतान की अवधि को बढ़ाकर पांच साल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 300 से ज्यादा जिलों के सिंचाई प्लान तैयार हो गए हैं और इस साल के अंत तक सभी जिलों के प्लान तैयार हो जाएंगे। इन प्लान को लागू करने के लिए अभी जो तीन अलग-अलग मंत्रालय इस मामले में राशि देते हैं, वे एकसाथ राशि देकर वहां सिंचाई व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा।

लोकसभा में सूखा और जल संकट की गूंज : लोकसभा में महाराष्ट्र के लातूर में सूखा और जलसंकट का मामला गूंजा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में हालात भयंकर हैं। केंद्र और राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शासनकाल के दौरान बड़े-बड़े बांधों से केवल चीनी उद्योग को ही फायदा हुआ है, किसानों को नहीं। कृषि मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 8 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सभी राज्यों को सूखा राहत आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक, ओडिशा तथा अन्य राज्यों को साल 2011-12 की तुलना में अधिक राशि आवंटित की है

प्र० प्रभारी समाचार पत्र यूनिट
लाइब्रेरी